जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 28 संख्याः 350 प्रभात अजमेर, शुक्रवार 19 जुलाई, 2024 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

हरियाणा में दोनों पार्टियों, कांग्रेस व भाजपा में विध्वंसक खेमेबाज़ी ''पीक'' पर!

- रेणु मित्तल -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है।

उन्होंने हरियाणा के एक कांग्रेस विधायक राव धनसिंह, जो भूपिन्दर सिंह हूड्डा के काफी नज़दीक माने जाते हैं, के पीछे ई.डी. लगा दी है। राव धनसिंह बहुत धनवान व्यक्ति हैं तथा महेन्द्रगढ़ से विधायक हैं।

राव ऐसे अकेले विधायक नहीं हैं। कांग्रेस के ही एक और बहुत धनवान विधायक, जो सीनियर हूड्डा के करीबी माने जाते हैं, भी संकट में आ चुके हैं। उनके बड़े पुत्र जेल में हैं तथा पिता और छोटे पुत्र भी भागे-भागे फिर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे भी ई.डी. लगी हुई है।

- कांग्रेस में हुड्डा खेमा व हुड्डा विरोधी खेमा, एक-दूसरे के कामों में शरीक ही नहीं हो रहे, बल्कि ए.आई.सी.सी. के महासचिव बाबरिया, जो प्रभारी भी हैं, पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं पक्षपात का।
- भाजपा में भी मु.मंत्री के खिलाफ एक बगावत सी स्थिति है तथा एक दूसरे के प्रति इतना अविश्वास व द्वेष है कि आशंका जताई जा रही है कि चुनाव के पहले ही भाजपा सरकार गिर ना जाये।
- साथ ही, कांग्रेस विधायकों, विशेषकर हुड्डा खेमे के विधायकों को ई.डी. के नोटिस आने शुरु हो गये हैं और घटनाक्रम को भी चुनाव सिर पर होने का लक्षण माना जा रहा है, कांग्रेस द्वारा।

हरियाणा में जबरदस्त गुटबाजी है तथा पार्टी में हूड्डा गुट का बोलबाला है तथा दूसरा गुट हूड्डा गुट का सहयोग करने के लिये तैयार नहीं है।

ए.आई.सी.सी. महासचिव इस खींचतान के एक असहाय दर्शक बन कर रह गये हैं। एक गुट पार्टी-प्रभारी बाबरिया पर आरोप लगा रहा है कि वे केवल एक ही गुट की तरफदारी एवं सहायता कर रहे हैं। भाजपा की अन्दरुनी स्थिति भी इतनी ही खराब है क्योंकि यह पार्टी कई गुटों में बँटी हुई है।

रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत होने वाली है। कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक कह रही हैं कि हरियाणा सरकार चुनावों से काफी पहले ही गिर सकती है।

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

जयपुर, 18 जुलाई (का.सं.)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवक को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने 25 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जबकि प्रकरण को लेकर एक किशोर का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। अभियुक्त युवक पीड़िता के पड़ोस में रहने वाली महिला का भाई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 16 जुलाई, 2020 को पीड़िता के चाचा ने नरेना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पूर्व रात को करीब डेढ़ बजे उसकी भतीजी बिना बताए कहीं चली गई है। उसे गांव और रिश्तेदारी में काफी तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। पीड़िता अपने साथ गहने, कपड़े और पहचान पत्र भी ले गई है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि वह किसी लड़के के साथ जा सकती है।

- पॉक्सो मामलों की अदालत ने आरोपी पर 1.75 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कांवड़ियों के परम्परागत मार्ग पर सभी दुकानों, ढाबों व थड़ियों को मालिक का नाम लिखना अनिवार्य होगा'

मुज़फ्फर नगर के इस नये आदेश से उथल-पुथल मची है, मार्ग पर स्थित दुकानों व ढाबों में

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जुलाई। इस वर्ष 22 जुलाई को शुरु होने वाली कांवड़िया यात्रा से कुछ दिन पूर्व ही उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने दुकानदारों, ढाबों एवं ठेला गाड़ी वालों को एक आदेश दिया है कि वे कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाली दुकानों के मालिकों तथा वहां काम करने वालों के नाम दुकान के बाहर प्रदर्शित करें।

इस आदेश को मुस्लिम दुकानदारों के खिलाफ कदम के रुप में देखा जा रहा है और इस आदेश को समुदाय विशेष का ''आर्थिक रुप से बहिष्कार'' करने के रुप में देखा जा रहा है।

कुछ समय पूर्व सम्पन्न लोकसभा चुनावों में भाजपा का असंतोषजनक प्रदर्शन होने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सियासी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांवड़ यात्रा पर जारी निर्देशों के कारण एक बड़ा राजनीतिक घमासान छिड़ गया है और कांग्रेस, ए.आई.एम.आई.एम. तथा समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर प्रदेश की सामाजिक व सांस्कृतिक परम्पराओं को ध्वस्त करने का आरोप लगाया है।

- कांग्रेस, सपा व ओवैसी की पार्टी ने इस आदेश को मुसलमानों का व्यापारिक दृष्टि से बायकॉट करने का प्रयास बताया।
- ओवैसी ने तो इस आदेश की तुलना दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति व नाज़ी जर्मनी में यहूदियों के सामान का बायकॉट करने की प्रक्रिया को दोहराना बताया।
- दारूल उलूम के प्रवक्ता ने इस बारे में कहा कि ''कांवड़ियों की पद यात्रा में मुसलमान व्यापारी सदा से उनकी सुविधा के लिये पानी व नाश्ते की व्यवस्था करते आए हैं और ऐसे ही हिन्दू समाज ताज़िये के जुलुस के दौरान सहयोग देता है। इस भाई-चारे को ''डिस्टर्ब'' नहीं करना चाहिये।''

इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद जिला प्रशासन ने यह कहते हुए बचाव किया कि ये दिशानिर्देश दुकानदारों व ठेला गाड़ी मालिकों के लिए ''स्वैच्छिक प्रकृति'' के हैं। हालांकि, दुकानदारों के साथ ही मुजफ्फरनगर की 240 कि.मी. कांवड़ यात्रा के मार्ग पर सभी विक्रेता बगैर कोई हुज्जत के सरकारी सूचना का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे फलों का ठेला लगाने वाले व दुकानदारों ने दुकान के बाहर बोर्ड पर ''आरिफ आमवाला'' व ''निसार फल विक्रेता'' लिखा हुआ था।

एक माह तक चलने वाले कांवड़ मेले के दौरान भगवान शिव के भक्तगण हरिद्वार की हर की पौड़ी से पवित्र जल कांवड़ में लेकर आते है तथा पैदल चलकर मध्य मार्ग में मुजफ्फरनगर से गुजरते हुए, आगे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में जाते है। पिछले कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा के मार्ग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

द्रमुक ने वंशवाद के नारे को धता बताया

मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि को उपमुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी

- लक्ष्मण वैंकट कुची -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जुलाई। तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डी.एम.के.) ने हमेशा अपने नेतृत्व के उत्तराधिकारी की योजना तैयार रखी है। द्रमुक के पितृपुरूष ने बड़े युक्तिसंगत तरीके से पार्टी नेतृत्व अपने छोटे पुत्र एम.के. स्टालिन को सौंप दिया था। उन्होंने अपने बड़े पुत्र एम.के. अलागिरी के बजाय अपने छोटे पुत्र का चयन एक ऐसे समय पर किया था, जब दोनों भाइयों के बीच की प्रतिद्वंदिता पार्टी को क्षति पहुँचाती दिखाई दे रही थी।

इसके विपरीत, इसके मुख्य प्रतिद्वन्दी दल अन्नाद्रमुक के पास उत्तराधिकारी की कोई योजना कभी नहीं रही तथा इसीलिये, पार्टी की ताकतवर एवं एकछत्र नेता जे जयललिता के निधन के बाद, पार्टी में बिखराव की स्थिति आ गई और आखिरकार उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा।

अन्नाद्रमुक आज भी अन्दरूनी फूट एवं संघर्ष से जूझ रही है तथा उसके टूटे हुये घटक उसे और भी कमजोर कर रहे हैं, जबकि द्रमुक को विभाजित हुये विपक्ष का लाभ मिल रहा है। इससे द्रमुक को अपनी ताजातरीन उत्तराधिकार-योजना को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। पार्टी के प्रथम परिवार ने दृढ़तापूर्वक पार्टी का भविष्य का नेता सुनिश्चित कर दिया। पार्टी ने सुस्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री तथा द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को उत्तराधिकारी मान लिया है।

इस योजना के क्रियान्वयन के संकेतों की विधिवत घोषणा उस समय होगी, जब, जैसी सम्भावना है, उदयनिधि स्टालिन को पदोन्नत कर उपमुख्यमंत्री बना दिया जायेगा तथा उन्हें योजना-क्रियान्वयन का प्रमुख मन्त्रालय सौंप दिया जायेगा। ज्ञातव्य है कि यह मन्त्रालय प्रमुख सरकारी योजनाओं, जिनमें अतिमहत्वपूर्ण जन-कल्याण योजनाएं भी शामिल हैं, का क्रियान्वयन करता है तथा उसकी देख-रेख करता है। उदयनिधि स्टालिन पहले ही, इस वर्ष जनवरी में ही, उपमुख्यमंत्री बनाये जाने वाले थे, लेकिन उस समय इस निर्णय को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था क्योंकि वे सनातन धर्म विवाद में उलझ गये थे। उस समय ऐसा सोचा गया था कि इस मुद्दे का पूरे भारत में इंडिया गठबन्धन की सम्भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, भले ही तमिलनाडु में द्रमुक को इससे मदद मिल जाती।

द्रमुक सूत्रों के अनुसार, करुणानिधि परिवार के वंशज अगले माह उपमुख्यमंत्री बना दिये जायेंगे। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाये तो उदयनिधि स्टालिन इस समय भी गैर-सरकारी तौर पर नम्बर दो ही हैं, लेकिन उपमुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नत हो जाने के बाद, उनका पार्टी का सम्भावित नेता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सूत्रों के अनुसार, उदयनिधि को इस वर्ष के आरम्भ में जनवरी में ही उपमुख्यमंत्री बनाया जाना था। पर, सनातन धर्म संबंधी उनके बयान और उस पर उभरे विवाद के कारण निर्णय रोक दिया गया, क्योंकि यह माना गया कि इससे लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की संभावनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता, हालांकि द्रमुक को यह विवाद अवश्य ही तमिलनाडू में भारी फायदा देता।
- द्रमुक की मुख्य प्रतिद्वंदी, अन्नाद्रमुक में कभी भी उत्तराधिकारी की घोषणा की योजना नहीं बनाई गई, यही वजह है कि जयललिता की मृत्यु के बाद से पार्टी में नेतृत्व विवाद चल रहा है और अन्नाद्रमुक को विभाजन तक झेलना पड़ा।
- अन्नाद्रमुक की कमजोरी और विभाजित विपक्ष का लाभ उठाते हुए द्रमुक ने उदयनिधि को उत्तराधिकारी बनाने की योजना पर काम शुरु कर दिया है।

आर.ए.एस. मेन्स में शामिल नहीं होंगे 569 अभ्यर्थी

जयपुर, 18 जुलाई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2023 की मुख्य परीक्षा में शामिल करने की मांग को लेकर 569 अपीलार्थियों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। हालांकि अदालत ने अपीलों पर सुनवाई चार सप्ताह बाद रखी है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने ये आदेश मुस्कान अग्रवाल व 38 अन्य याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि उत्तर कुंजी को तब तक सही माना जाना चाहिए, जब तक कि वह गलत साबित नहीं हो जाए। इसके अलावा कोर्ट विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर चुपचाप नहीं बैठ सकता है। अदालत में आने वाले 569 याचिकाकर्ताओं में से 476 ने निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ऐसे में यदि अपीलार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई तो पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी।

अपील में कहा गया कि आर.ए.एस. भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कुछ सवालों को गलत तरीके से जांचा गया था। एकलपीठ ने भी इन त्रुटियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहीं मुख्य परीक्षा 20 जुलाई को होने वाली है। ऐसे में यदि अपीलार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया गया तो वे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हाई कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों की अपील ठुकरा दी, हालांकि 4 सप्ताह बाद इन अपीलों पर सुनवाई का आदेश दिया है।

'सौ विधायक साथ में लाओ और नई सरकार बनाओ'

अखिलेश यादव ने भाजपा के असंतुष्ट विधायकों को अपना मानसून ऑफर दिया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जुलाई। उत्तर प्रदेश भाजपा में जारी हलचल व अशांति की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज इस घटनाक्रम का लाभ उठाने का प्रयास करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों से कहा कि राज्य में नई सरकार गठित करने के लिए वो पाला बदल लें।

एक्स पर एक रहस्यमय पोस्ट में उन्होंने लिखा, ''मानसून ऑफर: सौ लाओ सरकार बनाओ''.....

यादव ने हालांकि अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, तथापि, एक वरिष्ठ नेता ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि यह भाजपा के उन लोगों के लिए संदेश है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से असंतुष्ट व नाराज़ हैं तथा पाला बदलना चाहते हैं।

सपा नेता ने समझाया, ''सपा ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में एक सौ ग्यारह सीटें जीती थीं और यदि हमें भाजपा के सौ असंतुष्ट विधायकों का समर्थन मिल जाता है तो हम आसानी से सरकार बना सकते हैं।''

भाजपा की राज्य इकाई में फूट की अफवाहों में, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा बुधवार को एक्स पर डाली गई पोस्ट ने आग में घी का काम किया, जिसमें कहा था कि पार्टी सरकार से बड़ी है।

मौर्य ने सभी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करें।

मौर्य मंगलवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मिले थे, लेकिन ना तो भाजपा और ना ही उप मुख्यमंत्री ने मीटिंग के बारे में कुछ कहा।

काफी समय से चर्चा है कि, मौर्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- मु.मंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मु.मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच ज्यादा मधुर संबंध नहीं हैं, यह आम चर्चा है यू.पी. में।
- बुधवार को मौर्य ने ट्वीट करके कहा था कि पार्टी सरकार से बड़ी है। इस ट्वीट से उनका इशारा स्पष्ट रूप से मु.मंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर है।
- अखिलेश यादव इस मतभेद का लाभ उठाते हुए तर्क दे रहे हैं कि वर्तमान विधानसभा में सपा के 111 विधायक हैं तथा अगर भाजपा के असंतुष्ट 100 विधायक साथ आ जायें तो नई सरकार बनायी जा सकती है यू.पी. में।

सुप्रीम कोर्ट को मिले दो नए न्यायाधीश

नयी दिल्ली, 18 जुलाई। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने गुरुवार को न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत परिसर में आयोजित एक समारोह में दोनों न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों, अनेक वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

शीर्ष अदालत में न्यायाधीश बनने से पहले न्यायमूर्ति कोटिश्वर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति महादेवन मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सी.जे.आई. डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और जस्टिस आर. महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई।

यू.पी. भाजपा ने प्रदेश में पार्टी की शर्मनाक हार के 6 कारण बताए

रिपोर्ट में आंतरिक मतभेद को सबसे बड़ा कारण बताया गया है

- डॉ. सतीश मिश्रा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जुलाई। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में आन्तरिक मतभेद को देश के सबसे बड़े राज्य में पार्टी की अपमानजनक हार का मुख्य कारण बताया है।

हालांकि पार्टी ने रिपोर्ट में पेपर लीक, सरकारी नौकरियों पर संविदा पर नियुक्ति देना और राज्य प्रशासन की दमन नीति को भी प्रमुख कारण बताया है, जिसकी वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष फैला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थक और विरोधी गुट में स्पष्ट विभाजन देखा गया।

सपा-कांग्रेस गठबंधन, जिसने राज्य से लोकसभा की 80 सीटों में से 43 सीटे जीतीं और एन.डी.ए. की सीटों की संख्या 2019 की 64 से गिरकर 36 रह गई, की जीत के बाद राज्य भाजपा ने केन्द्रीय नेतृत्व को 15 पेज की विश्लेषण रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों ने संकेत दिया कि राज्य कि यह रिपोर्ट 40,000 लोगों से पार्टी प्रदर्शन के बारे में की गई वार्ता पर आधारित है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि केन्द्रीय नेतृत्व को निर्णायक कदम उठाने होंगे ताकि भावी चुनावों में अगड़े और पिछड़े वर्ग के बीच का संघर्ष बढ़ने से रोका जा सके।

हाल ही में यू.पी. भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वरिष्ठ नेताओं से मिले। उत्तरप्रदेश के अन्य बड़े नेताओं के साथ चर्चा की योजना भी है ताकि महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी की हार की समीक्षा से वृहद रणनीति बनाई जाए।

उल्लेखनीय है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा हार का कारण अति आत्मविश्वास को बताए जाने के बाद, पार्टी में अर्न्तकलह बढ़ गई है। मुख्यमंत्री के इस बयान का केशव प्रसाद मौर्य ने खण्डन किया और कहा कि पार्टी और संगठन व्यक्ति से बड़े होते हैं।

प्रदेश इकाई की रिपोर्ट में प्रशासन की दमनकारी नीति, पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष, पेपर लीक, संविदा भर्ती सहित 6 कारण बताए गए हैं। संविदा भर्ती को आरक्षण पर भाजपा के खिलाफ भी प्रमुख कारण बताया है, विपक्ष की बातों की पुष्टि होती है।

एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा कि विधायकों के पास कोई अधिकार नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अधिकारी ही सब कुछ हैं। इससे हमारे कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर रहे हैं। वर्षों से भाजपा व आर.एस.एस. ने साथ मिलकर काम किया व समाज से सम्बन्ध जोड़ा है। सरकारी अधिकारी कार्यकर्ता की जगह नहीं ले सकते हैं।

एक अन्य पार्टी नेता ने कहा कि गत तीन साल में 15 पेपर लीक हुए हैं और नौकरियों को संविदा से भरा जा हरा है, इससे विपक्ष के इन आरोपों की पुष्टि होती हैं कि भाजपा आरक्षण खत्म करने जा रही है।

भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने लखनऊ में मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भूपेन्द्र चौधरी व कई प्रमुख नेताओं से बातचीत की। भाजपा के एक पदाधिकारी ने कहा कि वार्ता के लिए प्रदेश नेताओं को अलग-अलग चरणों में बैठक के लिए बुलाया जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार पार्टी का जनाधार घटा है। कुर्मी व मौर्य वोट बैंक व दलितों का समर्थन खिसक गया है। रिपोर्ट ने माना है कि मायावती का जनाधार घटना और कांग्रेस प्रदर्शन में सुधार को भी हार का प्रमुख कारण बताया गया है।

सूत्रों ने कहा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश इकाई के मतभेदों को सुलझाना चाहिए तथा अगड़ा बनाम पिछड़ा मतभेद को उभरने से रोका जाना चाहिए।

जब यू.पी. में कल्याण सिंह का प्रभुत्व था, तब पार्टी को लोध समुदाय का समर्थन प्राप्त था लेकिन भाजपा का ओ.बी.सी. जनाधार वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी के आने के बाद बढ़ा।

प्रदेश इकाई ने माना कि टिकट वितरण जल्दी होने से पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू में चरम पर था पर छठे व सातवें दौर के आने तक पार्टी कार्यकर्ता थक गए एवं पार्टी नेताओं द्वारा आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी करने से भी प्रदर्शन पर असर पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार ओल्ड पेंशन स्कीम, अग्निवीर व पेपर लीक जैसे मुद्दे भी जनता के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिलों में सुरक्षा बलों ने चार दिनों में घुसपैठ की दूसरी कोशिश ना-काम की है।

घुसपैठ करते दो आतंकी मारे गए

श्रीनगर, 18 जुलाई। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने चार दिन में घुसपैठ की दूसरी कोशिश को नाकाम करते हुए गुरुवार को दो अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया।

सेना ने यह जानकारी दी और उसने बताया कि घुसपैठ की सूचना के बाद केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अभियान शुरू किया गया था।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इलाके में घुसपैठ की खुफिया सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। तलाशी अभियान के दौरान वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गयी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गये,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)